

भारत में संधारणीय शहरीकरण हेतु केरल मॉडल

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केरल भारत का पहला राज्य है, जिसने [तीव्र शहरीकरण](#) को संधारणीय रूप से प्रबंधित करने के लिये 25 वर्षीय रोडमैप के साथ एक [केरल शहरी नीति आयोग \(KUPC\)](#) की स्थापना की है।

- राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई **KUPC रिपोर्ट** ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि केरल मॉडल अन्य राज्यों के लिये विकास को जलवायु अनुकूल, शासन सुधार और वित्तीय सशक्तीकरण के साथ संतुलित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

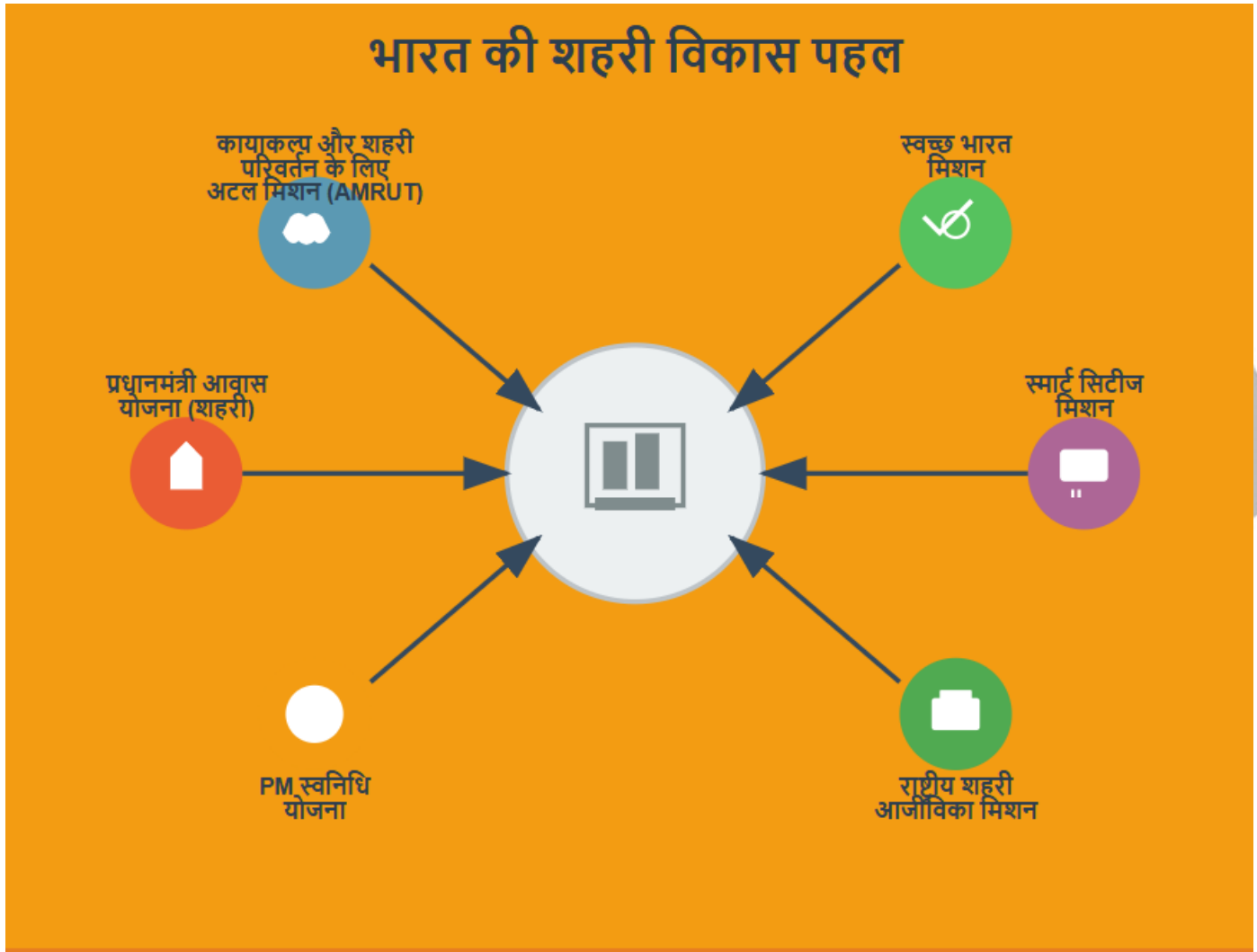
संधारणीय शहरीकरण के लिये KUPC रिपोर्ट की प्रमुख सफारिशें क्या हैं?

- केरल शहरी नीति आयोग (KUPC):** इसे केरल के शहरी भविष्य पर पुनर्विचार करने के लिये स्थापित किया गया था, जहाँ शहरों को केवल अवसंरचना समूह के रूप में नहीं, बल्कि जलवायु-सचेत पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखा गया है।
 - केरल का शहरीकरण वर्ष 2050 तक 80% से अधिक हो जाने की उम्मीद है और जलवायु जोखिम बढ़ रहे हैं, इसलिए **KUPC जलवायु अनुकूलन, वित्त, शासन, शहर की पहचान और समावेशी कल्याण** पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थान-आधारित रणनीति की सफारिश करता है।
- मुख्य सफारिशें:**
 - जलवायु-संवेदनशील शहरी योजना:** जोनल नियमों में खतरे के मानचित्रों (बाढ़, भूस्खलन, तटीय जोखिम) का उपयोग कर आपदा-प्रवण विकास को रोकना।
 - रीयल-टाइम शहरी डाटा प्रणाली:** नगरपालिकाओं को दशिया देने के लिये **लाइट डिटिकशन एंड रेंजिंग (LiDAR)** उपग्रह डाटा और मौसम सेंसर जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए एक डिजिटल प्रेक्वेंस केंद्र स्थापित करना।
 - ग्रीन शुल्क एवं जलवायु बीमा:** पारिस्थितिकी-संवेदनशील परियोजनाओं पर ग्रीन शुल्क लागू करना और लचीलापन व आपदा प्रतिक्रिया के लिये वित्त उपलब्ध कराने हेतु पैरामीटरिक जलवायु बीमा शुरू करना।
 - नगर नगिम और समेकित बॉण्ड:** प्रमुख शहर बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण हेतु **म्यूनिसिपल बॉण्ड (नगर नगिम बॉण्ड)** जारी कर सकते हैं, जबकि छोटे शहरों और कस्बों को इसके लिये समेकित बॉण्ड मॉडल अपनाना चाहिये।
 - शहरी प्रशासन सुधार:** महापौरों के नेतृत्व में नगरवाचक सटीक कैंबिनेट का गठन किया जाए। नगरपालिकाओं में अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों के लिये विशेषज्ञ टीमों का गठन किया जाए।
 - स्थानीय शासन में कुशल युवाओं की भरती के लिये “**ज्ञानश्री**” का शुभारंभ।
 - स्थान-आधारित शहरी विकास और समावेशी योजना:** प्रत्येक शहर की अनूठी शक्तियों को पहचानना तथा बढ़ावा देना (उदाहरण के लिये कोच्चि को फिनिटेक केंद्र के रूप में, त्रिवनंतपुरम एवं कोल्लम को नॉलेज कॉरिडोर के रूप में, कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में व पलक्कड़ और कासरगोड को स्मार्ट-औद्योगिक केंद्र के रूप में)।
 - स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक वारिसत को संरक्षित करने के लिये आर्द्रभूमि, जलमार्ग तथा वारिसत क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना।
 - प्रवासियों, गति श्रमिकों और छात्रों के लिये स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण सहायता प्रदान करने हेतु नगर स्वास्थ्य परिसरों की स्थापना करना, ताकि समान शहरी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।
 - समुदाय-आधारित डेटा:** यह दृष्टिकोण शहरी डेटा प्रणालियों में समुदायों के अनुभवों (जैसे मछुआरों और फुटपाथ विक्रेताओं के अनुभव) को सम्मिलित करने का समर्थन करता है, जिससे शहरी योजना अधिक सहभागी, समावेशी तथा ज़मीनी हकीकत पर आधारित बन सके।

भारत में शहरीकरण

- वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत की शहरी आबादी वर्ष 2036 तक **600 मिलियन (40%) तक पहुँच** जाएगी, जो **2011 में 31% थी**, तथा शहरों का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग **70% योगदान** होगा।
- भारत में शहरीकरण के प्रमुख चालक:
 - जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रवासन: नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बेहतर सुविधाओं से प्रेरित ग्रामीण-शहरी प्रवासन।

- कृषि संकट, घटती हुई भूमिजोत और जलवायु परिवर्तन परवासन को और बढ़ा रहे हैं।
- **आर्थिक परिवर्तन:** कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव। सूचना प्रौद्योगिकी, वनरिमाण तथा सेवाओं का वसितारशहरों को विकास, नवाचार एवं रोजगार का इंजन बनाता है।
- **नीतितगत प्रोत्साहन और शहरी मशिन:** स्मार्ट सिटी मशिन, अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मशिन), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) 2.0, और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शहरी अवसंरचना को नया आकार देते हैं, आवास में सुधार करते हैं, और उद्यमशीलता केंद्रों को बढ़ावा देते हैं।
- **प्रौद्योगिकी एकीकरण:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPIS) स्मार्ट शासन, कुशल सेवा वितरण और शहरों में बेहतर संसाधन प्रबंधन को सक्रम बनाते हैं।
- **वैश्वीकरण एवं आकांक्षाएँ:** वैश्विक बाजारों में एकीकरण और युवाओं की बढ़ती आकांक्षाएँ शहरी जीवनशैली, उपभोग पैटर्न और आधुनिक शहरी स्थलों की मांग को तेज करती हैं।
- पद्धतियों जैसे **कम्पोस्टिंग या फसल अवशेषों का बायो-ऊर्जा** में उपयोग करने के प्रतपरिप्राप्त अवसंरचना



केरल मॉडल भारत की शहरी योजना के लिये क्या उपाय प्रस्तुत कर सकता है?

- **स्मरण सूत्र (Mnemonic): KERALA**
- **K – (Knowledge & Community Data) ज्ञान एवं सामुदायिक डाटा:** उपग्रह और सेंसर डाटा को नागरिकों के इनपुट के साथ मलिकर नीतियों को इस तरह तैयार करना कि वे वास्तविक जीवन के अनुभवों को दर्शाएँ।
- **E – (Elected & Specialist Governance) नरिवाचति एवं वशिषज्ज शासन:** नौकरशाही पर नरिभर होने की वजह से हटकर नरिवाचति शहरी मंत्रमिंडल, वशिषज्ज नगरपालिका प्रकोष्ठ और युवा तकनीकी वशिषज्जों की ओर बढ़ना।
 - स्थानीय भूगोल, संस्कृत और जलवायु के अनुसार समयबद्ध शहरी आयोगों की स्थापना करना, केवल केंद्रीकृत ढाँचों पर नरिभर न रहना।
- **R – (Resilience & Climate Integration) अनुकूलन एवं जलवायु एकीकरण:** आपदा मानचित्रण और अनुकूलन को योजना के हर चरण का अभिन्न हस्सिा बनाना, न कबिाद में सोचना।

- **A – (Autonomy in Finances) वित्तीय स्वायत्तता:** नगरपालिकाओं को साझा बॉन्ड, ग्रीन फीस और जलवायु बीमा जैसे साधनों से वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।
- **L – (Livelihood & Land-sensitive Planning) आजीविका एवं भूमि-संवेदनशील योजना:** स्थानीय अनुकूलताओं पर आधारित क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों को बढ़ावा देना, साथ ही साझा संसाधनों, संस्कृति और वसिहत की रक्षा करना।
- **A – (Awareness & Citizen Participation) जागरूकता एवं नागरिक भागीदारी:** स्वैच्छिकता, सामुदायिक सहभागिता और शहरी नियोजन नरिण्यों में जनसहभागिता को मज़बूत करना।

स्मार्ट सिटीज मिशन

के बारे में

- आरंभ: 2015
- प्रकार: केंद्र द्वारा प्रायोजित
- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- कार्यान्वयन: शहर स्तर पर एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के माध्यम से।
- मिशन की समय सीमा: जून 2023 तक विस्तारित
- कवरेज: 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना

छह मूलभूत सिद्धांत

- मूल में नागरिक (Citizen at the core)
- कम-से-अधिक (More from Less)
- सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद (Cooperative and competitive federalism)
- एकीकरण, नवाचार, संवहनीयता (Integration, innovation, sustainability)
- प्रौद्योगिकी साधन के रूप में न कि लक्ष्य के रूप में (Technology as means, not the goal)
- अभिसरण (Convergence)

स्मार्ट समाधान

ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाएँ

- जन सूचना, शिकायत निवारण
- इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण
- नागरिक भागीदारी
- नागरिक - शहर की आँखें और कान
- वीडियो अपराध निगरानी



ऊर्जा प्रबंधन

- स्मार्ट मीटर और प्रबंधन
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत
- ऊर्जा कुशल और हरित भवन



अपशिष्ट प्रबंधन

- अपशिष्ट से ऊर्जा एवं ईंधन
- अपशिष्ट से खाद
- अपशिष्ट जल का उपचार
- निर्माण और विध्वंस (C&D) अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और कमी



शहरी आवागमन

- स्मार्ट पार्किंग
- कुशल यातायात प्रबंधन
- एकीकृत मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट



जल प्रबंधन

- स्मार्ट मीटर और प्रबंधन
- लीकेज की पहचान, निवारक प्रबंध
- जल गुणवत्ता की जाँच



अन्य

- टेली-मेडिसिन तथा टेली एजुकेशन
- इन्क्यूबेशन/व्यापार सुगमता केंद्र
- कौशल विकास केंद्र



■ अब तक 60 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं ■

चुनौतियाँ

- वित्त प्रबंधन: वित्त जुटाने, उन्हें SPV में स्थानांतरित करने तथा उनके कुशल उपयोग में कठिनाई
- शहरी समस्याएँ: जैसे वायु प्रदूषण, सड़क पर भीड़भाड़ और सार्वजनिक परिवहन में कमी
- नीतिगत मुद्दे: जैसे पर्यावरण अनापत्ति (Environment Clearances) प्राप्त करने में बाधा
- डेटा गोपनीयता और सुरक्षा
- केंद्र-राज्य समन्वय का अभाव

आगे की राह

- विकेंद्रीकरण: बेहतर कार्यान्वयन के लिये नगरपालिका और राज्य स्तर पर नियोजन
- नीतिगत मुद्दे: लालफीताशाही (अत्यधिक नियमों एवं नियंत्रण के कारण अनावश्यक विलंब) की तरह, पर्यावरण मंजूरी पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है
- PPP मॉडल: बेहतर प्रशासनिक एवं तकनीकी क्षमताओं के लिये
- समन्वित दृष्टिकोण: परिवहन, ऊर्जा, आवास के समग्र विकास हेतु
- नागरिक भागीदारी को बढ़ावा



Drishti IAS

समस्याएं: वायु प्रदूषण, सड़क पर भीड़भाड़ और सार्वजनिक परिवहन में कमी

प्रश्न: भारत की शहरी योजना प्रणाली को केवल नौकरशाही पर निर्भर रहने के बजाय सहभागी और क्षेत्र-वर्षि आधारित शासन की दशा में अग्रसर होना चाहिये। चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????:

प्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016)

प्रश्न. क्या कमजोर और पछिड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/kerala-model-for-sustainable-urbanisation-in-india>

